(a) whether it is a fact that apart from the 13 Laboratories under the ICAR coordinating Pesticides Residue Scheme, the CSIR Laboratories such as National Botanical Research Institute are also doing similar research in plants such as Pan leaves, Betel and Neem; if so, the details thereof indicating the foods, the farm products tested, the pesticides analysed and the results obtained;

(b) what are the achievements of the above collaboration and what measures have been taken to avoid the overlapping in the R and D involved; and

(c) whether there has been any exchange of views before embarking on these products?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) Sir, The research conducted in ICAR is complementary to the work being done in CSIR. While ICAR is laying more emphasis on pre-harvest residue analysis, CSIR is concentrating mainly on pesticide residues during the post-harvest phase. Research under ICAR has established tolerance limits and waiting periods for different pesticides being used in the country. In addition, neem products have been tested for various crop pests. The Central Food Technology Research Institute, CSIR is engaged in pesticide residue assessment in food and has developed technologies and formulations specific to conservation and protection of food as a part of post harvest technology chain. The National Botanical Research Institute of CSIR is carrying on investigations on pesticide residues in betel leaves as a part of its operational research project.

Demand for repeal of ESMA, etc.

*238. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a demand from the workers to repeal the Essential Services Maintenance Act and other anti-labour laws; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) and (b) Representations had been made in the past against the Trade Unions and the Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1988 which had been introduced in the Rajya Sahba on the 13th May, 1988. The subject came up for discussion in the 29th Session of the Indian Labour Conference held on 21st and 22nd April, 1990 and following that, a decision was taken to withdraw the aforesaid Bill. The Bill was formally withdrawn from the Rajya Sabha on 30th May, 1990. As far the Essential Services Maintenance Act (ESMA) is concerned, its present validity extends upto the 22nd September, 1990. A decision regarding further extension of its validity or otherwise will be taken before this date.

तिलहनों के उत्पादन में कठिनाइयां

*239. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मई, 1990 के "टाइम्स आफ इंडिया" में इनपुट शार्टेज हिटस आयल सीड्स आउटपुट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संयुक्त अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में तिलहनों के उत्पादन में पेश आ रही कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अच्छी किस्म के बीज, उर्वरकों और कीटनाशकों के उत्पादन की ओर कोई ध्यान दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो अगले तीन वर्षों के दौरान उन्नत बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के उत्पादन का वर्ष-वार कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार): (क) जी, हां।

(ख) किसी संयुक्त अध्ययन दल का गठन नहीं किया गया था। तथापि, कृषि मंत्रालय की एक मासिक पत्रिका "एग्रो-कल्चरल सिचुएशन इन इंडिया" के अक्तूबर, 1989 के अंक में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तीन अधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से एक लेख प्रकाशित किया गया था। इस लेख में दिये गये निष्कर्ष, जो इस समाचार पत्र में उद्धृत किये गये हैं, 1978-79 में मूंगफली उत्पादन में संसाधन उपयोगिता के बारे में किये गये एक नमूना सर्वेक्षण में एकत्र आंकड़ों पर आधारित है। बताया गया है कि नमूना सर्वेक्षण द्वारा कवर किये गये कुछ कृषकों ने बीज और जल के उपलब्ध न होने, उर्वरकों, वनस्पति रक्षण रसायनों की अधिक लागत तथा निधियों की कमी जैसे अवरोधों का उल्लेख किया है।

(ग) जी, हां। भारत सरकार ने तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित अवरोधों पर काबू पाने के लिये चार स्तरीय नीति के साथ मई, 1986 में एक तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की थी:-

-अधिक उत्पादक और लाभप्रद फसल प्रौद्योगिकी;

-कटाई के बाद की अधिक कुशल प्रौद्योगिकी;

-प्रौद्योगिकी के अंतरण के साथ कृषकों को प्रभावशाली समर्थन और फार्म आदानों को आपूर्ति; और

-कृषकों को प्रभावशाली मूल्य समर्थन और उद्योग को समर्थन ताकि कटाई के बाद की एक अधिक कुशल अवसंरचना का निर्माण किया जा सके।

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अधीन विभिन्न आदानों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 1990-91 के दौरान 69.972 करोड़ रुपये के परिव्यय में से भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ 75:25 की हिस्सेदारी के आधार पर 54.00 करोड़ रुपये राशि की व्यवस्था करेगी। इस राशि में से उन्नत/गुणकारी बीजों के उत्पादन और वितरण के लिये 30 प्रतिशत, पौध संरक्षण के लिये 27 प्रतिशत और जिप्सम/पाइराइट की आपूर्ति के लिये 5 प्रतिशत है। इस तरह महत्वपूर्ण आदानों, जिनका उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव है, की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तिलहन उत्पादकों को फसल ऋण प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सहायता से ऋण दिये जाने की विशेष व्यवस्था भी की गई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के माध्यम से मंडी में हस्तक्षेप की भी व्यवस्था की है।

(घ) **बीज**-1990-91 के लिये प्रमाणीकृत/गुणकारी बीजों के वितरण का लक्ष्य 10.00 लाख क्विंटल है।

उर्वरक-पोषकों के रूप में 1990-91 में उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य 90.75 लाख मीटरी टन, 1991-92 में 97.96 लाख मीटरी टन, 1992-93 में 101.97 लाख मीटरी टन और 1993-94 में 111.24 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

कीटनाशक-सभी अपेक्षित कीटनाशकों के लिये देश में पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। चयनित मामलों में आयात भी किया जाता है। सरकार कीटनाशकों के उत्पादन और उपलब्धता को ध्यान पूर्वक मोनिटरिंग करती है। सामान्यता देश में तिलहनों या किसी अन्य फसल के लिये कीटनाशकों की कोई कमी नहीं है।